

वन विभाग द्वारा निर्धारित मानक भातों के मान्य होने का प्रमाण-पत्र

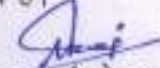
कार्य का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा भिक्यासैन के अन्तर्गत हरडा-भिक्यासैन मोटर मार्ग का नव निर्माण।

लंबाई - 17.400 किमी.

- 1- भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वनभूमि बनी रहेगी।
- 2- प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
- 3- याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
- 4- भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाय कि मांगी गयी न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
- 5- हस्ताक्षरी विभाग उसके कर्मचारी अधिकारी अथवा ठेकेदार वनभूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचेगी और ऐसा किए जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा जिसके याचक विभाग सहमत है।
- 6- भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देखरेख में करायेगी तथा इस सम्बन्ध में बनाए गए मुनारे आदि की देखभाल करेगा।
- 7- हस्ताक्षरित वनभूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्ताक्षरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 8- बहुमुल्य वन सम्पदा से आध्यापित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना संभव होगा, परन्तु प्रतिवर्ष यह होना कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
- 9- सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों, पौधों एवं विभाग के कर्मचारियों को नि: शुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
- 10- याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग, संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वनभूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापिस हो जायेगी। वन भूमि की आवृत्तता याचक विभाग को न रहने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
- 11- सड़क निर्माण के प्रस्तावों में एलाइनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा.नि.वि. द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस संबंध में प्रमुख अभियंता सा.नि.वि. के अतिरिक्त मुख्य अभियंता पर्वत क्षेत्र कुमायूँ को संबोधित पत्र सं० 608 सी० दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी सा.नि.वि. द्वारा किया जायेगा कि अ. वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को बदलकर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से प्राप्त न होना और नई सड़क का निर्माण आवश्यक है।

- 12- वन विभाग का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित ही होगा जो याचक विभाग को मान्य होगा।
- 13- वनभूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उ०प्र०, वन विभाग अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो विभाग को उचित समझे, द्वारा किया जाएगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा संभव न हो सके और उनका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
- 14- हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगुने गैरवानिकी क्षेत्रफल पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्षों तक परिपोशण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निश्चित है। इसी प्रकार बाँझ के वृक्षों का पालन भी विनिर्दिष्ट है। ऐसे वृक्षों का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर ही होगा।
- 15- वनभूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथासंभव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। खंभों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके संबंधित उपवनसंरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
- यदि नहर आदि निर्माण में भूसंरक्षण की आवश्यकता होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
- 16- उपरिलिखित मानक भातों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है। तो ये याचक विभाग को मान्य होंगी।
- 17- वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय जब उच्च भातों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका सुनिश्चित स्तर से आवासन प्राप्त हो जाय।
- 18- प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य हैं।


(प्रेमपाल सिंह)
अमीन
प्रान्तीय खण्ड, ल००/नि०वि०
रानीखेत


(मनोज शर्मा)
अपर सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, ल००/नि०वि०
रानीखेत


(एन.के.पन्त)
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, ल००/नि०वि०
रानीखेत


(डी.पी.सिंग)
अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, ल००/नि०वि०
रानीखेत